Proposal for "Saryu Action Plan"

*187. KUMARI ALIA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to undertake "Saryu Action Plan" on the pattern of the Ganga Action Plan;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(c) what are the details of survey conducted to find out pollution in the "Saryu River"?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) No, Sir.

(b) Under the Ganga Action Plan so far cities on the mainstream of the Ganga River itself have been taken up for pollution abatement schemes.

(c) There has been no survey conducted to find out the load of pollution in the Saryu River.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की अनौपचारिक शिक्षा योजना

***188. श्रीमती वीणा वर्मा :**
श्री कपिल वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से अनौपचारिक शिक्षा योजना चला रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब आरंभ की गई थी; इस योजना के तहत अब तक कितनी धनराशि का उपबंध किया जा चुका है और जिन राज्यों में उक्त योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि साक्षरता को प्रोत्साहन देने के लिए विदेशों से प्राप्त धन का, केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से पहले प्रौढ़ शिक्षा के लिए और बाद में परिवर्तित रूप में अनोपचारिक शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है । (नीचे देखिये)

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता :

विवरण

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से केन्द्र सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार द्वारा अनौपचारिक शिक्षा की कोई भी योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है । तथापि केन्द्र सरकार प्रारम्भिक स्तर पर प्रयोगात्मक तथा नई परियोजनाओं की सहायता की योजना के अन्तर्गत तथा अनौपचारिक शिक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेन्सियों तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है । ये योजनाएं वर्ष 1979-1980 में शुरू की गई थीं । राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान द्वारा वर्ष 1985 में किए गए मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की पालना करने हेतु प्राप्त अनुभवों के आधार पर वर्ष 1987 में इन योजनाओं को संशोधन किया गया था । पिछले 3 वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्य-वार संस्वीकृत धनराशि का विवरण अनुबंध में दिया गया है ।

अनुबंध

(लाख रु० में)

क्रम सं.	राज्य	वर्ष 1987–88, 1988–89 तथा 1989–90 के दौरान स्वैच्छिक एजेंसियों/संस्थाओं को मुक्त की गई धनराशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	138.32
2.	असम	14.39
3.	बिहार	76.84
4.	गुजरात	128.43
5.	हरियाणा	54.98
6.	हिमाचल प्रदेश	15.35
7.	कर्नाटक	5.40
8.	केरल	5.48
9.	मध्य प्रदेश	39.85
10.	महाराष्ट्र	168.56
11.	मणिपुर	3.98
12.	उड़ीसा	502.14
13.	राजस्थान	81.78
14.	तमिलनाडु	42.80
15.	उत्तर प्रदेश	139.03
16.	पश्चिम बंगाल	64.13
17.	दिल्ली	77.79
18.	चंडीगढ़	2.27*

* संघ शासित प्रशासन को मुक्त की गई धनराशि